

प्रेषक,

आर०के०तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ०२ अगस्त 2015

विषय:- मुख्य वन संरक्षक(कार्य योजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक (शोध) एवं वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र संख्या-2205/2-34 दिनांक 22.4.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक (शोध) एवं वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण के प्राक्कलन लागत ₹485.04 लाख की टी.ए.सी. से परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत ₹436.61 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख इक्सठ हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु शासनादेश संख्या-ख-248/X-2-2010-12(13)/2010 टी०सी० दिनांक 20.9.10 द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त ₹40.13 लाख तथा शासनादेश संख्या-80(A)/X-2-2014-12(54)2012 दिनांक 15.1.2014 द्वारा अवमुक्त द्वितीय किस्त ₹82.40 लाख, जो शासनादेश संख्या-620/X-2-2014-12(85)/2012 दि० 26.03.2014 के संदर्भ में वन जमा में जमा है, कुल अवमुक्त ₹122.53 लाख (एक करोड़ बाईस लाख त्रेपन हजार) की धनराशि के सापेक्ष वन जमा में जमा धनराशि ₹82.40 लाख को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उक्त आगणन की लागत ₹436.61 लाख में से ₹12.18 लाख के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार कराये जायेंगे।
2. उक्त कार्य हेतु वन जमा में जमा धनराशी ₹82.40 लाख तत्काल कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. योजना हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20.9.2010 द्वारा अवमुक्त ₹40.13 लाख के सापेक्ष निर्माण इकाई द्वारा ₹5.87 लाख व्यय किया गया है एवं शेष ₹34.26 लाख की धनराशि निर्माण इकाई के पास उपलब्ध है, पर अर्जित ब्याज तत्काल राजकोष में जमा करते हुये शासन को सूचित किया जायेगा।
4. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासनादेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर शासन को अवगत कराया जायेगा।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
7. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने पर तदनुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
 10. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2009) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
 12. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
 13. विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दि० 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) आवश्यक हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम०ओ०यू० के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम०ओ०यू० में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम०ओ०यू० में निर्धारित शर्तों के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य का समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने में का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4406-वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परियोजना, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण और विकास, 04-वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०प०संख्या-48(P)/XXVII(4)/2015 दिनांक 27 अगस्त 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०के०तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या-2037 / X-2-2015-12(45) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर०के०तोमर)
संयुक्त सचिव